

संपादकीय भटकी हुई योजना

यह वाकई चिंता की बात है कि सांसद निधि का सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। केंद्रीय सारियकी और कार्य म कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी डेटा के अनुसार साल 2014 से अब तक 543 में से केवल 35 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में ही सांसद निधि का इस्तेमाल कर स्वीकृत प्रॉजेक्ट पूरे किए गए हैं। परियोजनाओं में विलंब को देखकर केंद्र सरकार इसकी फाँड़िग के तरीके में बदलाव पर विचार कर रही है। अभी इसके तहत राशि दो किस्तों में दी जाती है। सरकार एक किस्त में ही राशि आवंटित करने के बारे में सोच रही है।

सांसद निधि योजना (एमपीएलैड स्कीम) की शुरूआत 1993 में हुई, जब पी.वी. नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे। इसके तहत सभी एमपी को, चाहे वे लोकसभा के हों या राज्यसभा के, अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्य कराने के लिए प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता दी जाती है। इसका मकसद विकास कार्यों का विकेंद्रीकरण करना था। सोचा गया कि जनहित के बे छेटे-छेटे कार्य जो बड़ी परियोजनाओं में समाहित नहीं हो पाते, इसके जरिए आसानी से कम समय में हो सकेंगे। पर सच्चाई यह है कि इस योजना की राशि जरूर बढ़ी गई, लेकिन इससे जनता को खास लाभ नहीं हो पाया है। इसमें भारी श्रावाचार के भी आरोप लगते रहे हैं। इसलिए एक तबका इसे समाप्त करने की श्री सलाह देता है। कुछ सांसद इसके सफल न होने के पीछे नौकरशाही को जिम्मेदार ठहराते हैं।

इस योजना की राशि सांसद के खाते में नहीं बिल्कु संबंधित जिसे के जिलाधिकारी या किसी अन्य नोडल अधिकारी के खाते में जाती है। वितर्व के शुरू होने के पहले यह राशि 2.5 करोड़ रुपये की दो किस्तों में भेजी जाती है। सांसद, जिलाधिकारी को बताता है कि उसे जिसे में कहां-कहां इस राशि का उपयोग करना है। ऐसी व्यवस्था इसलिए की गई कि कोई एमपी मनमाने ढंग से इसे खर्च कर सके। लेकिन सांसदों का कहना है कि जिलाधिकारी के रवैये के कारण प्रॉजेक्ट लटकते हैं। एक किस्त मिलने के बाद जब तक उसका यूटीलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं जमा किया जाता तब तक दूसरी किस्त जारी नहीं होती। कई कारणों से जिला प्रशासन द्वारा यह सर्टिफिकेट जमा करने में देरी होती है।

तमिलनाडु से पाण्डाली मकल कटिय (पीएमके) के सांसद अंमुमणि रामदास का आरोप है कि पिछले चार साल में वह अपने क्षेत्र के कलवर्त के रवैये के कारण किसी भी योजना को ठीक से लागू नहीं कर पाए। शहरी इलाकों में जमीन निलापन के कारण भी विकास कार्य अटका रहता है। इस कारण पैसे जारी नहीं हो पाते। कई सांसद मानते हैं कि एक किस्त में पैसे देने से भी समस्या नहीं सुलझेगी। एक सलाह यह भी है कि इसका सोशल ऑफिट हो। सरकार इसके सारे पहलुओं पर विस्तर से विचार करे और जरूरत हो तो इसमें आमूल परिवर्तन कर।

2019 का पहला सूर्यग्रहण 6 जनवरी को, जाने सूर्य और चंद्र ग्रहण के दिखाएं कितने नजारे

नया साल 2019 आने वाला है। नहीं देगा। दूसरा सूर्य ग्रहण- 2019 का दूसरा सूर्य ग्रहण 2 जुलाई के दिन लगेगा। यह पूर्ण ग्रहण होगा। लेकिन

यह ग्रहण भी भारत में दिखाई नहीं देगा। तीसरा सूर्य ग्रहण- साल 2019 का तीसरा और अखिरी सूर्य ग्रहण 26 दिसंबर को पड़ेगा।

यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। तीसरा सूर्य ग्रहण- साल 2019 का तीसरा और अखिरी सूर्य ग्रहण 26 दिसंबर को पड़ेगा।

यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। तीसरा सूर्य ग्रहण- साल 2019 का तीसरा और अखिरी सूर्य ग्रहण 26 दिसंबर को पड़ेगा।

यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। तीसरा सूर्य ग्रहण- साल 2019 का तीसरा और अखिरी सूर्य ग्रहण 26 दिसंबर को पड़ेगा।

यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। तीसरा सूर्य ग्रहण- साल 2019 का तीसरा और अखिरी सूर्य ग्रहण 26 दिसंबर को पड़ेगा।

यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। तीसरा सूर्य ग्रहण- साल 2019 का तीसरा और अखिरी सूर्य ग्रहण 26 दिसंबर को पड़ेगा।

यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। तीसरा सूर्य ग्रहण- साल 2019 का तीसरा और अखिरी सूर्य ग्रहण 26 दिसंबर को पड़ेगा।

यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। तीसरा सूर्य ग्रहण- साल 2019 का तीसरा और अखिरी सूर्य ग्रहण 26 दिसंबर को पड़ेगा।

यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। तीसरा सूर्य ग्रहण- साल 2019 का तीसरा और अखिरी सूर्य ग्रहण 26 दिसंबर को पड़ेगा।

यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। तीसरा सूर्य ग्रहण- साल 2019 का तीसरा और अखिरी सूर्य ग्रहण 26 दिसंबर को पड़ेगा।

यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। तीसरा सूर्य ग्रहण- साल 2019 का तीसरा और अखिरी सूर्य ग्रहण 26 दिसंबर को पड़ेगा।

यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। तीसरा सूर्य ग्रहण- साल 2019 का तीसरा और अखिरी सूर्य ग्रहण 26 दिसंबर को पड़ेगा।

जानिए अचारी गोभी बनाने की विधि



खाद्यानुसार नमक छिकें और अच्छी तरह से मिला लौंतेल गर्म होने पर उसमें गोभी के टुकड़े डालें और डीप फ्राइ कर ले। उसके बाद तली हुई गोभी को किचने पेर पर निकल ले। फ्राइ पैन में एक बड़ा चमच तोल छोड़ कर बाकी का तेल निकल दें। गर्म तेल में आमचूर पाउडर और मिर्च पाउडर छोड़ कर सारे मसाले डाल दें और अच्छी तरह से भूल ले। मसाले भूल जाने पर पैन में गोभी के टुकड़े, आमचूर पाउडर डालें और अच्छी तरह से चला ले। उसके बाद गैस बंद कर दें।

अगर खो गया आधार कार्ड तब भी mAadhaar के जरिए आसानी से हो जाएगा आपका काम

नई दिल्ली। आधार कार्ड अब केवल पहचान पत्र नहीं रह गया है। इसकी जरूरत पहचान के लिए किसी भी विलंब को देखकर केंद्र सरकार इसकी फाँड़िग के तरीके में बदलाव पर विचार कर रही है। अभी इसके तहत राशि दो किस्तों में दी जाती है। सरकार एक किस्त में ही राशि आवंटित करने के बारे में सोच रही है।

यह वाकई चिंता की बात है कि सांसद निधि का सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। केंद्रीय सारियकी और कार्य म कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी डेटा के अनुसार साल 2014 से अब तक 543 में से केवल 35 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में ही सांसद निधि का इस्तेमाल कर स्वीकृत प्रॉजेक्ट पूरे किए गए हैं। परियोजनाओं में विलंब को देखकर केंद्र सरकार इसकी फाँड़िग के तरीके में बदलाव पर विचार कर रही है। अभी इसके तहत राशि दो किस्तों में दी जाती है। सरकार एक किस्त में ही राशि आवंटित करने के बारे में सोच रही है।

यह वाकई चिंता की बात है कि सांसद निधि का सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। केंद्रीय सारियकी और कार्य म कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी डेटा के अनुसार साल 2014 से अब तक 543 में से केवल 35 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में ही सांसद निधि का इस्तेमाल कर स्वीकृत प्रॉजेक्ट पूरे किए गए हैं। परियोजनाओं में विलंब को देखकर केंद्र सरकार इसकी फाँड़िग के तरीके में बदलाव पर विचार कर रही है। अभी इसके तहत राशि दो किस्तों में दी जाती है। सरकार एक किस्त में ही राशि आवंटित करने के बारे में सोच रही है।

यह वाकई चिंता की बात है कि सांसद निधि का सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। केंद्रीय सारियकी और कार्य म कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी डेटा के अनुसार साल 2014 से अब तक 543 में से केवल 35 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में ही सांसद निधि का इस्तेमाल कर स्वीकृत प्रॉजेक्ट पूरे किए गए हैं। परियोजनाओं में विलंब को देखकर केंद्र सरकार इसकी फाँड़िग के तरीके में बदलाव पर विचार कर रही है। अभी इसके तहत राशि दो किस्तों में दी जाती है। सरकार एक किस्त में ही राशि आवंटित करने के बारे में सोच रही है।

यह वाकई चिंता की बात है कि सांसद निधि का सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। केंद्रीय सारियकी और कार्य म कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी डेटा के अनुसार साल 2014 से अब तक 543 में से केवल 35 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में ही सांसद निधि का इस्तेमाल कर स्वीकृत प्रॉजेक्ट पूरे किए गए हैं। परियोजनाओं में विलंब को देखकर केंद्र सरकार इसकी फाँड़िग के तरीके में बदलाव पर विचार कर रही है। अभी इसके तहत राशि दो किस्तों में दी जाती है। सरकार एक किस्त में ही राशि आवंटित करने के बारे में सोच रही है।

यह वाकई चिंता की बात है कि सांसद निधि का सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। केंद्रीय सारियकी और कार्य म कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी डेटा के अनुसार साल 2014 से अब तक 543 में से केवल 35 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में ही सांसद निधि का इस्तेमाल कर स्वीकृत प्रॉजेक्ट पूरे किए गए हैं। परियोजनाओं में विलंब को देखकर केंद्र सरकार इसकी फाँड़िग के तरीके में बदलाव पर विचार कर रही है। अभी इसके तहत राशि दो किस्तों में दी जाती है। सरकार एक किस्त में ही राशि आवंटित करने के बारे में सोच रही है।

यह वाकई चिंता की बात है कि सांसद निधि का सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। केंद्रीय सारियक